कॉलेजों में दोबारा सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू करेगा यूजीसी

सेमेस्टर सिस्टम खत्म होने से छात्रों का हो रहा नुकसान

इंदौर/भोपाल। नईदुनिया प्रतिनिधि

यूजीसी प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों की यूजी कक्षाओं में दोबारा सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू करने जा रहा है। यूजीसी का मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम समाप्त होने से न सिर्फ छात्रों का नुकसान हो रहा है, बल्कि छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य छात्रों से पिछड़ भी रहे हैं।

सेमेस्टर सिस्टम दोबारा लागू करने के लिए यूजीसी के चेयरमैन प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखने जा रहे हैं। नईदुनिया से विशेष चर्चा में उन्होंने इसी महीने पत्र लिखकर राज्य सरकार से दोबारा सेमेस्टर सिस्टम लागू करवाने की मांग करने की बात कही है। वहीं इस बारे में कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के पहले कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर भर्ती और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहिए।

यूजीसी के चेयरमैन इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग को लिखेंगे पत्र

दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने मप्र में साल 2009 में यूजीसी के निर्देश पर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था, इसके करीब आठ साल बाद 2017 में इस सिस्टम को खत्म कर दोबारा से एनुअल सिस्टम लागू कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम के तहत छात्रों को साल में दो बार परीक्षा देनी होती है, जबकि एनुअल सिस्टम में साल में सिर्फ एक बार परीक्षा होती है। विभिन्न छात्र संगठनों के अलावा छात्र और प्रोफेसर भी सेमेस्टर सिस्टम को खत्म कर दोबारा एनुअल सिस्टम लागू किए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने 2 साल पहले सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन यूजीसी का यह मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम कई देशों की शिक्षा व्यवस्था को देखने के बाद बनाया गया था, इसे खत्म करने से छात्रों को नुकसान हो रहा है।

8 साल पीछे हो गए छात्र

यूजीसी ने कई देशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद सेमेस्टर सिस्टम तैयार किया था। प्रदेश में इसे खत्म कर छात्रों को 8 साल पीछे धकेल दिया गया है। मैं इसी महीने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस सिस्टम को दोबारा लागू किए जाने की मांग करूंगा।

-प्रो. डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी

छात्र और प्रोफेसर मानसिक रूप से नहीं हैं तैयार

प्रदेश प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. कैलाश त्यागी का कहना है कि मप्र का माहौल सेमेस्टर सिस्टम के लायक नहीं है। यहां के कॉलेजों में 13000 प्रोफेसरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 5000 प्रोफेसरों के भरोसे सरकारी कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं।

विद्यार्थियों से 21 को संवाद करेंगे मंत्री जीतू पटवारी

इंदौर। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नए आयामों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सीधे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम 21 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक्षशिला परिसर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा। इसमें संभाग के सरकारी और निजी कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल होंगे।

परीक्षा विभाग ने बनाया प्रस्ताव, कई यूनिवर्सिटीज में है लागू

1500 रुपए चार्जेस देंगे तो 24 घंटे में मिल जाएगी अर्जेन्ट डिग्री

दबंग रिपोर्टर ■ इंदौर

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में अर्जेन्ट डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डिग्री बनाने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें लगभग 15 दिन का समय लगता है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी अर्जेन्ट डिग्री चाहने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अलग सेल की योजना बना रही है। इसके लिए विद्यार्थी से 1500 रुपए शुल्क लेने का प्रस्ताव है। सामान्य रूप से 200 रुपए शुल्क लिया जाता है। देश की कई यूनिवर्सिटी में अर्जेन्ट डिग्री, माइग्रेशन आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

परीक्षा विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्ज्वल खरे के अनुसार तुरंत डिग्री चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्याबढ़ रही है। लोक सेवा गारंटी योजना में डिग्री देने का समय 15 दिन निश्चित किया है। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर एडमिशन व नौकरी चाहने वाले विद्यार्थियों तुरंत डिग्री चाहते हैं।

अलग बनाएं अर्जेन्ट डिग्री का सेल

यूनिवर्सिटी कई बार ऐसे विद्यार्थियों की मदद नहीं कर पाती है। अब परीक्षा विभाग ने इसके लिए अलग सेल बनाने की योजना बनाई है। इस सेल के कर्मचारी अर्जेन्ट डिग्री तैयार करने का काम करेंगे। योजना है कि डिग्री विद्यार्थी को 24 घंटे में दे दी जाए। सामान्य रूप से डिग्री का शुल्क 200 रुपए लगता है लेकिन अर्जेन्ट डिग्री के लिए 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का शुल्क प्रस्तावित है।